सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 259 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 02 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

वीबी जी-राम-जी अधिनियम पर मीडिया वार्ता कल

रायपुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर द्वारा विकसित भारतङ्गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर एक महत्वपूर्ण मीडिया वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 जुलाई 2026 को प्रात: 11 बजे रायपुर के सिविल लाइंस स्थित न्यू सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा। इस मीडिया संवाद में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। वहीं ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा (रायपुर) के प्रोफेसर आनंद रघुवंशी मुख्य वक्ता के रूप में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन ढांचे पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

आकाशीय बिजली से बीजापुर में 9 बकरियों की मौत

बीजापुर। जिले के चेरकंटी सरहद के कोटेर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में एक पशुपालक की नौ पालतू बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। यह घटना उस समय हुई जब बकरियां खुले क्षेत्र में चर रही थीं। अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आने से सभी नौ बकरियां तुरंत मर गईं। इस दुखद घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, इस क्षति का आकलन भी किया जा रहा है।

स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूलों में मंत्रोच्चार कराए जाने के राज्य शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सिंगल बेंच ने फिलहाल यह कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि अभी तक आदेश के लागू होने का कोई ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है। इस मामले में पूर्व वक्फबोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी ने याचिका लगाई थी। याचिका में राज्य शासन के आदेश को संविधान का उल्लंघन बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. अमीर खान ने पैरवी की।

नई सुबह : बीजापुर में 21 साल बाद खुले 11 स्कूल, 539 बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। माओवादी आतंक से वीरान पड़े पीडिया क्षेत्र में 21 वर्षों बाद स्कूलों की घंटियां फिर से गूंजी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कलेक्टर विश्वदीप की पहल पर 11 स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू हुआ है। इससे 11 गांवों के 539 बच्चों को अपने ही गांव में शिक्षा का अधिकार मिला है। यह स्कूलों का पुन: खुलना भय से विश्वास और अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ते बस्तर की नई पहचान है।

पीडिया में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षादूतों को सामग्री और बच्चों को स्कूल बैग वितरित कर उनका स्वागत किया। जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम और जनपद उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों का तिलक लगाकर और लड्डू खिलाकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जानकी कोरसा ने कहा कि शिक्षा विकास की मजबूत नींव है।

37 स्कूलों का पुनः संचालन

जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि कलेक्टर विश्वदीप की पहल पर बंद स्कूलों को पुन: संचालित करने का अभियान जारी है। इस वर्ष अब तक 20 प्राथमिक और 17 उच्च प्राथमिक, कुल 37 स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू हो चुका है। कलेक्टर विश्वदीप ने कहा कि प्रत्येक गांव तक शिक्षा पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

21 साल बाद लौटी शिक्षा

सलवा जुडूम के दौरान माओवादी हिंसा के कारण पीडिया क्षेत्र के कई स्कूल बंद हो गए थे। उनके भवन भी ध्वस्त कर दिए गए थे। अब पीडिया, पेदापाल, छोटेगोटोडी, कुएम, मदपाल, अंडरी, इडेनार, डोंडीतुमनार, मिरगानघोटूल, गमपुर और तमोड़ी गांवों में विद्यालय फिर से शुरू हुए हैं।

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में होगी 700 प्राध्यापकों की भर्ती, उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में निर्णय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को नया कलेवर देने और सालों से अटके प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्री टंक राम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है।

इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। महाविद्यालयों में प्रशासनिक

कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए।

पदोन्नति का रास्ता साफ

प्राध्यापकों और विभागीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। साल 2019 से पहले के बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लगभग तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं

बजट प्रबंधन को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। अब किसी भी कॉलेज को बजट जारी करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। नए महाविद्यालयों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ताकि किसी को भी कम या ज्यादा राशि मिलने की शिकायत न हो।

छात्र बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी

महाविद्यालयों में 90 घंटे, 90 दिन का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स चलाया जाएगा। इस अनूठे अभियान से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के भीतर का संकोच दूर होगा और वे देश-दुनिया के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला सकेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट के लिए 226 करोड़ स्वीकृत

■ दुर्ग से ताड़ोकी के बीच 13 स्टेशनों के बीच लगेगा सिस्टम

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेल (एसईसीआर) के रायपुर मंडल के दुर्ग-ताडोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई) प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली से बदलना शामिल है, जिससे सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-आधारित ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा।

स्वीकृत परियोजना में रायपुर डिवीजन के दुर्ग-तारोकी खंड के मारौदा, रिसमा, गुंडरदेही, लाटाबोर, बालोद, कुसुमकासा, दल्लीराजहरा, गुदुम, भानुप्रतापुर, केवटी, अंतागढ़, ताडोकी स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना शामिल है। पैनल इंटरलॉकिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में परिवर्तन से इस महत्वपूर्ण खंड पर सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का काफी आधुनिकीकरण होगा, जिससे परिचालन में अनुकूलन और सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली एक अत्याधुनिक सिग्नलिंग तकनीक है जो उन्नत सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करते हुए रूट सेटिंग और सिग्नलिंग कार्यों को स्वचालित बनाती है।

छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिन भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से लगभग 60 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में होने वाली व्यापक बारिश से वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी होने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश पर कई मौसमी प्रणालियां एक साथ प्रभाव डाल रही हैं। पंजाब से लेकर उत्तर बंगाल की

खाड़ी तक फैली मौसमी द्रोणिका, बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण तथा उत्तर छत्तीसगढ़ के आसपास बना एक अन्य चक्रवाती सिस्टम वर्षा को मजबूत कर रहा है। इन परिस्थितियों के चलते 3 जुलाई के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश का दौर और तेज हो सकता है।

राजधानी रायपुर में बुधवार की तरह गुरुवार को भी आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है। बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिले हैं।

बड़ी साजिश नाकामः आईएसआई से जुड़े चार आतंकी गिरफ्तार, एनसीआर भी था निशाने पर

■ अंतर-राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई प्रायोजित एक अंतर-राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से तीन पंजाब से और एक दिल्ली से है। ये आरोपी दिल्ली में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शुभदीप सिंह, गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत के रूप में हुई है। इन्हें आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के निर्देश पर काम करने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर उन्हें पाकिस्तानी हैंडलरों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

स्पेशल सेल ने आरोपियों के पास से दो विदेशी पिस्तौल और नौ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा, पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एक आरोपी गगनप्रीत को दिल्ली में पुलिस प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी करने का काम सौंपा गया था। उसे दिल्ली में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का भी निर्देश दिया गया था।

स्पेशल सेल को पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी द्वारा दिल्ली-एनसीआर में आतंकी घटना की योजना की विश्वसनीय जानकारी मिली थी। इनपुट से पता चला कि उन्होंने पंजाब से युवाओं की भर्ती की थी। खुफिया जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर दिल्ली और पंजाब में कई छापे मारे गए। पहली गिरफ्तारी अमृतसर से शुभदीप सिंह की हुई, जिसके पास से एक पिस्तौल, पांच कारतूस और दो मोबाइल फोन मिले। पूछताछ में उसने ड्रोन के जरिये हथियार और नशीले पदार्थ मिलने की बात कबूली। जांच के दौरान शुभदीप के दो सहयोगी गुरजंट सिंह और साजन सिंह को पंजाब से पकड़ा गया। उनके पास से एक जिगाना पिस्तौल, चार कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। बाद में, 24 अप्रैल, 2026 को गगनप्रीत को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। गगनप्रीत को पाकिस्तानी हैंडलरों ने दिल्ली में पुलिस थानों और पिकेट की वीडियो बनाने का काम दिया था।

चलती ट्रेन में बीएसएफ के हेड-कॉन्स्टेबल को जहर दिया : काठगोदाम रेलवे स्टेशन में मिला शव

देहरादून। उत्तराखंड के एक जवान को चलती ट्रेन में जहर दे दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बीएसएफ के हेड कॉन्स्टेबल सत्यपाल सिंह के रूप में हुई है। वह हरिद्वार के रुड़की के रहने वाले थे और जैसलमेर में तैनात थे।

29 जून की सुबह ट्रेन के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जनरल डिब्बे में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा मिला। जीआरपी ने उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पहले पुलिस ने शव को अज्ञात समझकर कार्रवाई में ढिलाई बरती, लेकिन मंगलवार को मृतक की जेब में रखे आधार कार्ड से उनकी पहचान होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक, सत्यपाल सिंह इन दिनों जैसलमेर में 20 वीं बटालियन में तैनात थे।

चरण पादुका खरीद टेंडर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रस्तावित करीब 50 करोड़ रुपए के चरण पादुका (जूते-चप्पल) खरीद टेंडर पर रोक लगा दी है। आरोप है कि इस मामले में न तो बोर्ड की औपचारिक स्वीकृति ली गई और न ही खरीद प्रक्रिया पर विस्तृत विचार-विमर्श कराया गया। प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरुप नहीं हुई, जिससे विवाद की

स्थिति बनी और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा।

बता दें कि प्रदेश के लगभग 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने के लिए बड़े पैमाने पर खरीद प्रक्रिया शुरु की गई थी। इसके लिए जारी टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस खरीद प्रक्रिया में विभागीय नियमों और संस्थागत प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया गया। सामान्यत: इतनी बड़ी वित्तीय खरीद से पहले प्रस्ताव संचालक मंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए था, ताकि उस पर चर्चा और अनुमोदन हो सके।

बेंगलुरु के खदान में बड़ा हादसा, चट्टान गिरने से बिहार के सात श्रमिकों की मौत

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार को एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा हो गया। एक विशाल चट्टान गिरने से बिहार के सात श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह दुखद घटना सुबह तड़के हुई। यह हादसा बेंगलुरु साउथ तालुक के मदापट्टाना स्थित एक पत्थर खदान में हुआ। मृतक सभी दिहाड़ी मजदूर थे और वे एक पत्थर क्रशर स्थल पर काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, ये श्रमिक गिरी हुई चट्टान के नीचे फंस गए और मौके पर ही उनकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब मजदूर खदान के संचालन कार्य में लगे थे। हादसे की सूचना मिलते ही

बचाव कर्मी और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया।

घायलों का उपचार और घटनास्थल पर कार्रवाई

घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, शुरुआती रिपोर्टों में कई श्रमिकों के घायल होने का संकेत मिला है। घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि अभी की जा रही है। अधिकारियों ने मलबे को हटाने का काम शुरू किया। वे यह पता लगाने में जुट गए कि कहीं कोई अन्य श्रमिक तो मलबे में नहीं फंसा है। पूरे क्षेत्र को तुरंत सील कर दिया गया था ताकि बचाव कार्य सुचारु रूप से चल सके।

संपादकीय

सड़न को ठीक करें

सरकारी नौकरियों और घोटालों का गहराता जाल

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को अक्सर कदाचार, उच्च-पदस्थ सरकारी अधिकारियों के उस बिकाऊपन से जोड़ कर देखा जाता है जिसमें वे खुद को या अपने करीबियों को मालामाल बनाने के लिए रिश्वत लेते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन पर असर डालने वाला इसका ज्यादा नुकसानदेह रूप वह है जिसमें सार्वजनिक परीक्षाओं व भर्तियों को सुव्यवस्थित तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि तेजी से आधुनिक हो रही अर्थव्यवस्था में, जहां नौकरियां कौशल और प्रशिक्षण पर लगातार ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, सार्वजनिक परीक्षाएं और शिक्षक भर्ती कुशल व्यक्तियों को तैयार करने का जरिया हैं। इन प्रक्रियाओं, जिन्हें आदर्श रूप में योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, में भ्रष्टाचार से जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फायदा उठाने की भारत की क्षमता का क्षरण होगा। चाहे मेडिकल स्नातक आकांक्षियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट का दोबारा आयोजन हो, या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का तय तारीख (28 जून) से ठीक पहले टाला जाना, यह बीमारी निराशाजनक रूप से जानी-पहचानी लगती है। इसके पीछे एक कुटीर उद्योग है जो अंदरूनी नेटवर्कों के जरिये पेपर लीक करता है और पास होने के लिए शॉर्टकट ढूंढ़ने वालों से मोटा पैसा बनाने के लिए विशाल कोचिंग इकोसिस्टम को लक्ष्य करता है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र मामले का कथित मुख्य सरगना — पटना का एक बाशिंदा जिस पर साल 2024 में ओडिशा पेपर लीक घोटाले और यहां तक कि नीट घोटाले से भी जुड़े होने का शक है — बिहार और हरियाणा से ऐसी टीमें चलाता था जो कोचिंग क्लासेज को पेपर बेचने की कोशिश करती थीं।

> “ इन प्रक्रियाओं, जिन्हें आदर्श रूप में योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, में भ्रष्टाचार से जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फायदा उठाने की भारत की क्षमता का क्षरण होगा। चाहे मेडिकल स्नातक आकांक्षियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट का दोबारा आयोजन हो, या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का तय तारीख (28 जून) से ठीक पहले टाला जाना, यह बीमारी निराशाजनक रूप से जानी-पहचानी लगती है। इसके पीछे एक कुटीर उद्योग है जो अंदरूनी नेटवर्कों के जरिये पेपर लीक करता है और पास होने के लिए शॉर्टकट ढूंढ़ने वालों से मोटा पैसा बनाने के लिए विशाल कोचिंग इकोसिस्टम को लक्ष्य करता है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र मामले का कथित मुख्य सरगना — पटना का एक बाशिंदा जिस पर साल 2024 में ओडिशा पेपर लीक घोटाले और यहां तक कि नीट घोटाले से भी जुड़े होने का शक है — बिहार और हरियाणा से ऐसी टीमें चलाता था जो कोचिंग क्लासेज को पेपर बेचने की कोशिश करती थीं। रहस्यमयी रूप से, एक के बाद एक घोटाले में एक जैसा पैटर्न सामने आया है।

रहस्यमयी रूप से, एक के बाद एक घोटाले में एक जैसा पैटर्न सामने आया है। गुजरात में, कनिष्ठ-लिपिक भर्ती परीक्षा 2023 के पेपर लीक का कथित मास्टरमाइंड हैदराबाद के उस छापाखाने का कर्मचारी था जिसने पेपर छापा था। साल 2024 में, जम्मू-कश्मीर में एक छापाखाने के अंदरूनी आदमी और सुरक्षा कर्मियों पर, सर्विसेज बोर्ड परीक्षा 2022 लीक मामले में, आरोपपत्र दायर किया गया। राजस्थान में, दिसंबर 2022 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर एक सेवारत सरकारी शिक्षक द्वारा बेचे गये। सारे मामलों में जो चीज समान है, वह है अंदरूनी नेटवर्कों की मौजूदगी जिन्होंने सिस्टम को चकमा देने के तरीके ढूंढ़ निकाले हैं। कमजोरी केवल प्रश्नपत्रों के वितरण के तरीके में नहीं है, बल्कि उन्हें सेट करने के तरीके में भी है, जहां विशेषज्ञों के चुनिंदा समूहों को बार-बार इस काम में शामिल किया जाता है ङ्क कई का तो कोचिंग इकोसिस्टम से जुड़ाव है। यही कारण है कि सरगनाओं को खोजने और जनता का ध्यान हटने तक दिखावटी जांच चलाने के इस कर्मकांड से असल समस्या अनछुई रह जाती है। मामले से जुड़े असल सवालों पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। क्या प्रश्नपत्र हर बार परीक्षकों के उसी पूल द्वारा सेट किया जाता है? क्या उनकी पृष्ठभूमि और कारोबारी रिश्तों का सत्यापन किया जाता है? क्या ये परीक्षाएं कराने वाले विभाग परीक्षकों के हितों के टकराव की जांच-पड़ताल करते हैं? आखिरी बात, अगर सिस्टम ऐसे सुधार कर ले, तो भी जवाबदेही के बिना वह अपूर्ण रहेगा। केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को अपनी नाकामियां कबूल करनी चाहिए। जब पेपर लीक की घटनाएं अभी की तरह नियमित रूप से होने लगें, तो इस सिस्टम की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

परिवर्तन की जड़ें: ई-गवर्नेंस से बदलता ग्रामीण भारत

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

कुछ क्षण केवल एक उपलब्धि भर नहीं होते, वे एक पूरी यात्रा को रोशन कर देते हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चार पंचायती राज पहलों का चयन ऐसा ही एक क्षण है, ऐसा क्षण जो किसी एक कार्यालय का नहीं, बल्कि हर ग्राम पंचायत और हर उस नागरिक का है, जिसने डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण भारत के सपने पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर, भारत की पंचायतें भरोसे, तकनीक और परिवर्तन का एक नया अध्याय लिख रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के बारह परिवर्तनकारी वर्षों के इस पड़ाव पर यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित निकायों से आगे बढ़कर, शासन की तीसरी स्तरीय व्यवस्था की आत्मविश्वासी, सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं के रूप में स्थापित हुई हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्कृष्ट लोक सेवा वितरण के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष सात श्रेणियों में चयनित 17 परियोजनाओं में से 4 पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित हैं, जो ज़मीनी स्तर पर नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पिछले बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है।

ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स , को डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के आने से पहले, देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कोई मानकीकृत, डेटा आधारित राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध नहीं था। आज यह सूचकांक डेटा, प्रदर्शन, पहचान और जनभागीदारी को आपस में जोड़ने वाली एक पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।

उल्लेखनीय यह है कि दो ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के प्रयासों से यह सम्मान अर्जित किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडेपुर ग्राम पंचायत ने ग्रासरूट स्तर की पहलों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से 1,300 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, पश्चिम त्रिपुरा की बिजय नगर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला है। पंचायत ने अपने स्वयं के स्रोतों से आय में लगभग 194 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और महिलाओं के बीच शत-प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल की है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग को 'ई-आरोग्य धमनी' पहल के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया।

ये पुरस्कार मिलकर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता अब केवल राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समान रूप से हमारे गांवों और ग्राम सभाओं में भी स्थापित हो चुकी है। इस वर्ष 30 राज्यों की 1.65 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया, जो हमारे द्वारा मिलकर तैयार की गई संस्थागत क्षमता और विश्वास को दर्शाता है।

यह उपलब्धि संयोग से नहीं मिली है। पिछले बारह वर्षों में मंत्रालय ने पंचायतों को निरंतर बेहतर साधन उपलब्ध कराए हैं। ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.59 लाख से अधिक पंचायतों में योजना निर्माण, बजट और भुगतान प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ?3.16 लाख करोड़ से अधिक के ऑनलाइन लेन-देन संभव हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सभासार प्लेटफॉर्म, जो 23 भारतीय भाषाओं में कार्य करता है, अब 1.35 लाख से अधिक पंचायतों में चंद मिनटों में ग्राम सभा की कार्यवाही तैयार कर देता है। मेरी पंचायत ऐप, जिसे 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, विकास कार्यों की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुंचा रहा है।

इन प्रयासों के साथ-साथ, स्वामित्व योजना के तहत 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा जून 2026 के मध्य तक 1.94 लाख गांवों के लिए 3.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकार सुदृढ़ हुए हैं और उन्हें ऋण सुविधा प्राप्त करने में आसानी हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.82 लाख करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है। सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 से 2031 के लिए 4.35 लाख करोड़ की सिफारिश की है, जो लगभग 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 'सेवा से समृद्धि: पंचायतों के नेतृत्व में सेवा वितरण' विषय पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। इन कार्यशालाओं में पंचायत प्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और विषय विशेषज्ञ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से सफल स्थानीय पहलों और नवाचारों को साझा किया जा रहा है, ताकि राज्य एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और अच्छे मॉडलों को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सके। इनकी उपयोगिता और विस्तार की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। 2026 में चयनित पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां देशभर की पंचायतों को प्रेरित कर रही हैं, और अनेक पंचायतें अपने गांवों में बेहतर सेवाएं पहुंचाकर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे मॉडलों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदैव यह बल देते रहे हैं कि सुशासन वही है जो नागरिकों का जीवन सरल बनाए। पारदर्शी और तकनीक सक्षम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त 'ईज़ ऑफ लिविंग' ही किसी सरकार की मंशा और क्षमता की सच्ची कसौटी है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि दूसरों का सम्मान करना स्वयं के सम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है। पंचायतों को डिजिटल साधनों से सशक्त बनाकर और उनकी क्षमता पर विश्वास जताकर, केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण मंच पर देश को सम्मानित होने का मार्ग प्रशस्त किया है।

जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, सशक्त पंचायतों की भूमिका और भी केंद्रीय होती जा रही है। लगभग 90 करोड़ नागरिकों के ग्रामीण भारत में निवास करने के साथ, हमारी पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती ही हमारी सामूहिक प्रगति की गति तय करेगी। विकसित पंचायत, विकसित भारत से अलग नहीं, बल्कि उसकी सबसे मजबूत नींव है।

ये चार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार बेहतर प्रदर्शन, प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने के प्रतीक हैं। ये जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे प्रत्येक सरपंच, पंचायत सचिव और महिला जनप्रतिनिधि के लिए एक प्रेरणा हैं कि उनके समर्पण और प्रयासों को पहचान मिल रही है, उनकी सराहना की जा रही है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों ने ही ऐसी उत्कृष्टता के उभरने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। NAeG 2026 में मिली पहचान से लेकर देशभर में बढ़ती सेवा से समृद्धि कार्यशालाओं की गति तक, यह सफलता इस बात की पुष्टि करती है कि ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस की जड़ें वास्तव में गहरी हो चुकी हैं, और विकसित पंचायत के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की यह यात्रा हर गुजरते वर्ष के साथ और सशक्त होती जा रही है।

लेखक केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री हैं।

ये पृथ्वी हमारा बड़ा घर है, अपने घर की तरह इसे भी साफ-सुथरा रखें

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी

हमारे दो घर होते हैं- एक छोटा और एक बड़ा। एक घर तो वह चारदीवारी है, जिसे हम अपना घर मानते हैं। उसमें हमारा सोफा होता है, डाइनिंग टेबल होती है, बिस्तर होता है। हम इस छोटे घर का विशेष ध्यान रखते हैं। उसे साफ रखते हैं और उसे सहेजते हैं, क्योंकि वह हमें सुरक्षा देता है। वह हमें धूल, गर्मी, ठंड, हवा और बारिश से बचाता है।

इसी तरह हमारा एक बड़ा घर भी है, हमारी धरती का वातावरण। यह भी हमें सुरक्षा देता है। यदि यह बड़ा घर न हो, तो सूर्य की किरणें इतनी तीव्र हों कि हम उन्हें सहन न कर सकें। या धरती का तापमान इतना कम हो जाए कि यहां जीवन सम्भव न रहे। परंतु इसके बावजूद- क्या कारण है कि हम अपने इस बड़े घर का ध्यान नहीं रखते?

यदि पर्यावरण में बहुत अधिक गर्मी हो जाए, बहुत अधिक ठंड पड़ जाए, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका असर हम पर पड़ता है। कुल मिलाकर पर्यावरण में जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन हम जो कुछ करते हैं, उसका प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है।

वास्तव में, आधुनिक जीवन में मनुष्य का शायद ही कोई ऐसा कार्य है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव न पड़ता हो। और दुर्भाग्य से, हमारे अधिकांश कार्य पर्यावरण को सकारात्मक नहीं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह पर्यावरण, हमारा यह बड़ा घर, हमें जीवन देता है।

यही हमें हवा देता है, पानी देता है, भोजन देता है और जीवन जीने योग्य परिस्थितियां प्रदान करता है। लेकिन बदले में हम इसे क्या देते हैं? हम इसे गंदा करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण डालते हैं। जब-जब हम खाना पकाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तब-तब हम कार्बन डाइऑक्साइड रूपी अदृश्य कचरा पर्यावरण में छोड़ते हैं, जो धरती के तापमान को बढ़ाने का काम करता है।

हम सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण फैक्टरियों से होता है। नहीं, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में फैक्टरियों में बनाए सामान के अनियंत्रित उपभोग के कारण होता है। हम सब रोज ही, या सच कहें तो हर मिनट ही अदृश्य कचरा फेंककर वातावरण रूपी हमारे बड़े घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एक बार मैंने अपने एक व्याख्यान में श्रोताओं से कहा, मैं आप सभी को थोड़ा-थोड़ा कचरा देता हूं। क्या आप इसे अपने घर ले जाकर अपने ही घर में फेंक देंगे? सबने तुरंत मना कर दिया। किसी ने कहा, पत्नी डांटेगी। किसी ने कहा, मां नाराज हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा, जब हम अपने छोटे-से घर में भी कचरा नहीं फेंक सकते, तो अपने उस बड़े घर में कचरा कैसे फेंक देते हैं, जो हमें जीवन देता है?

आज देश-दुनिया में बेमौसम बारिश हो रही है, ठंडे यूरोप में जानलेवा हीटवेव चल रही है, जंगलों में आग लग रही है। मौसम का जो यह असंतुलन हम देख रहे हैं, वह प्रकृति की प्रतिक्रिया है। यह प्रकृति का हमें यह बताने का तरीका है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि यदि आप प्रकृति होते, तो शायद आप भी सभी को ऐसी ही सजा देते। आखिर हम उसके घर में कचरा जो फैला रहे हैं, उसके संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य बना रहे।

जो कचरा हम धरती पर फेंक रहे हैं, उसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। यह कटु सत्य हमें होश में लाने के लिए है। हो सकता है इसी से हमारा पर्यावरण सुधार का सही काम चालू हो जाए। और हम सीमित धरती- जिसके संसाधन भी सीमित हैं- पर अपनी जरूरतों को भी सीमित करने की शुरुआत कर दें।

जलवायु सुधार टेक्नोलॉजी या नियम-कानून से शुरू नहीं होता। यह जागरूकता से शुरू होता है। संयम से शुरू होता है। यह हममें से हर एक द्वारा अपने बड़े घर के साथ उसी सम्मान से पेश आने से शुरू होता है, जैसा हम अपने बेडरूम के साथ करते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

थोक महंगाई ने दी खतरे की घंटी, क्या अर्थव्यवस्था पर गहराने वाला है नया संकट?

रंजना मिश्रा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से हाल में जारी एक रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2026 में थोक महंगाई दर में भारी उछाल दर्ज किया गया और यह 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गई है। अगर हम इसकी तुलना अप्रैल 2026 से करें, तो तब यह दर लगभग 8.3 प्रतिशत के करीब थी। केवल एक महीने के भीतर महंगाई का इतनी तेजी से ऊपर जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। यह आंकड़ा देश के हर एक नागरिक, हर छोटे-बड़े व्यापारी और हर उद्योग पर पड़ने वाले सीधे असर की ओर इशारा करता है। महंगाई ने न केवल देश के शीर्ष नीति-निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि आम जनता के घर के बजट को भी पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

दरअसल, थोक महंगाई मुख्य रूप से वह दर है, जिस पर थोक बाजार में चीजों की बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री होती है। यानी जब कोई बड़ा कारखाना या उत्पादक अपना तैयार माल थोक विक्रेताओं या वितरकों को बेचता है, तो वस्तुओं की कीमतों में जो बदलाव आता है, उसे इसी दर से मापा जाता है। हालांकि, आम आदमी सीधे तौर पर थोक बाजार से सामान नहीं खरीदता है, लेकिन अर्थशास्त्र का यह नियम है कि जब थोक में सामान महंगा होता है, तो कुछ ही समय बाद खुदरा बाजार में भी उसी अनुपात में दाम बढ़ जाते हैं। थोक महंगाई आज की कड़वी सच्चाई है, जिसकी आंच कल आम आदमी की रसोई और जेब तक तेजी से पहुंचने वाली है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई को मापने के इस पारंपरिक तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है। लगभग 14 वर्षों बाद थोक महंगाई सूचकांक के आधार वर्ष को पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले यह आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था, लेकिन अब इसे अद्यतन कर वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आज की बदलती अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर को सामने लाना है।

इतना ही नहीं, पहले के सूचकांक में सिर्फ 697 वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखी जाती थी, लेकिन अब नई प्रणाली में 957 अलग-अलग वस्तुओं को शामिल कर लिया गया है। इस नए सूचकांक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु बिजली को पहली बार शामिल किया गया है। इसके साथ ही, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर 'ईंधन और ऊर्जा' के समूह में डाल दिया गया है। सरकार ने इस मूल्य निर्धारण प्रणाली को दुनिया के विकसित देशों के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए और अधिक पारदर्शी तरीके से 'प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स' (पीपीआई) की शुरुआत भी की है।

सवाल है कि थोक महंगाई ने अचानक इतनी तेज छलांग क्यों लगाई? दरअसल, थोक महंगाई की इस आग में सबसे ज्यादा घी डालने का काम ईंधन की कीमतों ने किया है। नई रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि मई 2026 में ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की महंगाई दर 30.33 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 24.89 प्रतिशत थी। इसका प्रमुख कारण पश्चिम एशिया में चल रहा भू-राजनीतिक तनाव और देशों के बीच का संघर्ष है। जब भी दुनिया के उस संवेदनशील हिस्से में अशांति होती है, जहां से पूरी दुनिया को कच्चा तेल मिलता है, तो ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेश से ही खरीदता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल ने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर दिया है।

दूसरी ओर, खाद्य महंगाई हमेशा से भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में संवेदनशील मुद्दा रही है, क्योंकि एक आम भारतीय परिवार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने-पीने की बुनियादी चीजों पर ही खर्च होता है। रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में खाने-पीने की चीजों की थोक महंगाई दर भी तेजी से उछलकर 4.49 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 3.11 प्रतिशत के स्तर पर थी। अगर हम सिर्फ प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के सूचकांक को देखें, तो यह दर 3.60 प्रतिशत तक जा पहुंची है। यानी अनाज, फल और दूध जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी थोक मंडियों में तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से तिलहन और मसालों की कीमतों में भारी उछाल देश भर में चिंता का विषय बना हुआ है।

इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण जिम्मेदार हैं। पहला, माल ढुलाई का महंगा होना, क्योंकि किसानों के खेतों से निकलकर मंडियों और फिर दुकानों तक अनाज पहुंचाने में डीजल का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। दूसरा बड़ा कारण मौसम की अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन है। पिछले कुछ समय में कम बारिश, बेमौसम बरसात और बढ़ते तापमान ने कृषि उत्पादन पर काफी बुरा असर डाला है।

इस महंगाई का एक और बेहद गंभीर पहलू हमारे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये छोटे उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं और सबसे अधिक रोजगार इन्हीं क्षेत्रों से पैदा होता है। जब बड़े कारखानों में महंगाई बढ़ती है, तो उनके पास अक्सर इतना पैसा और बाजार की शक्ति होती है कि वे उस झटके को सह सकें या उसे आसानी से ग्राहकों तक पहुंचा सकें, लेकिन छोटे उद्योगों के पास यह सुविधा नहीं होती।

जब किसी छोटे कारखाने को कच्चे माल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है और साथ ही उसे परिवहन और बिजली का भी भारी बिल चुकाना पड़ता है, तो उसका थोड़ा-बहुत मुनाफा भी खत्म हो जाता है। अगर वह अपनी चीजों की कीमत बहुत बढ़ा देता है, तो आम ग्राहक उसे खरीदना बंद कर देते हैं और बड़ी कंपनियों के उत्पाद खरीदने लगते हैं। इस दोहरी मार से कई छोटे कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। जब ये बंद होते हैं, तो वहां काम करने वाले श्रमिकों का रोजगार भी छिन जाता है।

किसी व्यक्ति का रोजगार जाने का मतलब है कि उस पूरे परिवार की सामान खरीदने की क्षमता खत्म हो जाना। जब लोग बाजार से सामान खरीदना कम कर देते हैं, तो मांग तेजी से घट जाती है और जब मांग घटती है, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ने लगती है।

थोक महंगाई की यह नई रिपोर्ट केवल बढ़ती कीमतों का एक साधारण संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारे उद्योग जगत के सामने खड़े एक बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी भी है। जब तक ऊर्जा की अपनी जरूरतों के लिए भारत की निर्भरता दूसरे देशों के कच्चे तेल पर ज्यादा बनी रहेगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था इसी तरह विदेशी झटकों का शिकार होती रहेगी। इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि भारत को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ाने होंगे, ताकि वह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

बीएसपी में ई-5 और ई-6 के 110 अधिकारियों को पदोन्नति मिली

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र में संयंत्र के ई-5 और ई-6 स्तर के कुल 110 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। ई-6 से ई-7 में पदोन्नत 27 अधिकारियों को इस्पात भवन स्थित निदेशक प्रभारी सभागार में निदेशक प्रभारी चित्त रंजन महापात्र ने पदोन्नति आदेश वितरित किए। प्रक्रिया के तहत ई-5 से ई-6 में 83 अधिकारी पदोन्नत हुए, जिनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के 7 अधिकारी शामिल रहे। वहीं ई-6 से ई-7 में 27 अधिकारी पदोन्नत किए गए, जिनमें इसी विभाग के 3 अधिकारी शामिल हैं। महापात्र ने कहा कि नए पद के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप बड़े लक्ष्य तय कर काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादन जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सेल में स्वयं की उन्नति के बहुत अवसर मिलते हैं, जो आप सभी को मोटिवेट करते हैं और यही मोटिवेशन आपके निष्पादन में परिवर्तित होने से कंपनी को इसका लाभ मिलेगा।

मंत्री गजेंद्र ने बोरसी तक बन रहे फोरलेन का जायजा लिया

दुर्ग। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दुर्ग के महाराजा चौक से बोरसी तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। मंत्री गजेन्द्र ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति मिली है। सड़क, पुल एवं अन्य जनोपयोगी अधोसंरचनाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे दुर्ग के नागरिकों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और प्रत्येक निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करना सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के नागरिकों और वाहन चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह कार्य दुर्ग शहर के सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेगी।

पल्स पोलियो अभियान सफलतापूर्वक संपन्न

दुर्ग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ''पल्स पोलियो अभियान'' की समस्त सूक्ष्म कार्ययोजना के अनुरूप कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन एवं समस्त शहरी एवं ग्रामीण खण्ड चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के लक्षित 257134 के विरुद्ध 254118 बच्चों को पोलियो दवा पिला कर 99 प्रतिशत सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। डॉ. दिव्या श्रीवास्तव द्वारा विस्तार से बताया गया, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 05 वर्ष के बच्चों को 28 जून 2026 को निर्धारित बूथ पर 208518 तथा 29 जून 2026 को 31457 व 30 जून 2026 को 14143 घर-घर भ्रमण कर छूटे हुए कुल 254118 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई गई।

कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों से कलेक्टर सिंह ने किया संवाद

दुर्ग। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके दस बच्चों (प्रीति टंडन, करीना टंडन, स्पनिल बोस, दुष्यंत कुमार साहू, जयंत कुमार साहू, वैभव बंजारे, सुल्ताना खान, यमुना ठाकुर, जय ठाकुर, रविन्द्र कुमार टंडन) से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आत्मीय मुलाकात कर संवाद किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हुए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली।

कलेक्टर श्री सिंह ने बच्चों से उनके वर्तमान विद्यालय, पढ़ाई की स्थिति और रुचियों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने यह भी जाना कि बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति की उपलब्धता और शासन द्वारा दी जा रही अन्य सहायता योजनाओं के बारे में भी बच्चों से सीधे जानकारी ली। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएम केयर्स में लाभान्वित बालक/बालिकाओं को स्पांसरशिप योजना, महतारी दुलार योजना, एक्सग्रेसिया (आपदा प्रबंधन राहत कोष), 23 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुश्त 10 लाख रूपए की राशि, कक्षा पहली से 12वीं तक अध्ययनरत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 20 हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सभी बच्चों के आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के वोटर आईडी कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी बच्चों से उनकी वर्तमान पढ़ाई और शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। बच्चों ने अपने-अपने अध्ययन और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान कलेक्टर ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, लक्ष्य निर्धारित करने तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास के अधिकारी अजय साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति डांगरे, परियोजना समन्वयक चंद्रप्रकाश पटेल, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कर्मचारी उपस्थित थे।

घास जमीन को पशुपालन के लिए सुरक्षित करने ग्रामीणों ने की मांग

रिहायशी बस्ती से पोल्ट्री फार्म हटाने ग्रामवासियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 180 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में प्राप्त विभिन्न आवेदनों पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और उक्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में धुमा के ग्रामवासियों ने घास जमीन को पशुपालन के लिए सुरक्षित करने आवेदन दिया। ग्रामवासियों ने बताया कि तहसील पाटन के अंतर्गत घास जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। यह जमीन पशुओं के चरने के लिए सुरक्षित है और यदि अतिक्रमण जारी रहा तो गांव में मवेशियों के लिए चारागाह की समस्या और बढ़ जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं रुका। उन्होंने घास जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर पशु चारागाह के रूप में सुरक्षित रखने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

ग्राम थनौद के ग्रामीणों ने आवासीय क्षेत्र से लगे पोल्ट्री फार्म को बंद करने अथवा अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र के बेहद निकट संचालित हो रहा है, जिससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली दुर्गंध, अपशिष्ट और प्रदूषण के कारण पूरे गांव का वातावरण प्रभावित हो रहा है। इससे सांस लेने में परेशानी, मच्छर-मक्खियों का प्रकोप बढ़ने और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। गर्मी और बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराकर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने, पोल्ट्री फार्म को रिहायशी क्षेत्र से हटाने तथा जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत दुर्ग को निरीक्षण कर कार्यवाही करने को कहा।

ग्राम खम्हरिया के किसानों ने धनोरा नाला पर बने कट बांध के कारण खेतों में जलभराव होने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि धनोरा नाला पर बने कट बांध की वजह से हल्की बारिश में भी करीब 20 एकड़ कृषि भूमि में पानी भर जाता है, जिससे रोपा और बुवाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे खेती और आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ेगा। किसानों कट बांध का निरीक्षण कर जलभराव की समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

इंदु आईटीआई स्कूल में छात्रों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग पुलिस की यातायात शाखा ने इंदु आईटीआई स्कूल, कुरूद रोड में विद्यार्थियों के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के महत्व और नियमों के पालन पर विस्तार से समझाइश दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना किसी भी मोटर वाहन का संचालन कानून के विरुद्ध है।

दोपहिया चलाते समय हेलमेट और चारपहिया में सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यातायात संकेतों और संकेतकों का सम्मान करने पर जोर दिया गया। साथ ही सड़क पर सतर्क, संयमित और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की व्यावहारिक बातें साझा की गईं। यातायात शाखा ने विद्यार्थियों से नियमों का पालन करने और परिवार व आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की।

उक्त जागरूकता कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं विद्यार्थियों को यातायात नियमों के संबंध में प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने में यातायात शाखा, दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस आमजन से अपील करती है कि सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करें, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन संचालित न करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

दुर्ग में सेवानिवृत्त 7 पुलिस कर्मियों का सम्मान किया

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दुर्ग में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे सात अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान व विदाई का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिजनों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

इनमें उप निरीक्षक शिवनारायण सिंह, दीनदयाल वर्मा, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सोनी, राजकुमार दीवान, 5. प्रधान आरक्षक नंद कुमार सिंह, लवण सिंह, यदुलाल पाटिल शामिल रहे। करीब 35 से 40 वर्षों की सेवा पूरी कर विदा हो रहे कर्मियों ने अपने अनुभव साझा किए और अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा व जनसेवा के महत्व पर बात रखी। विभाग की ओर से उनके दीर्घकालीन योगदान की सराहना करते हुए उज्ज्वल, स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की गई। विदाई समारोह के संचालन व व्यवस्थाओं में कार्यालय और पुलिस लाइन के अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दुर्ग तथा पुलिस लाइन के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस अपने सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के दीर्घकालीन समर्पण, अनुशासन एवं जनसेवा के योगदान का सम्मान करती है तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन की मंगलकामनाएँ व्यक्त करती है।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी

1. उप निरीक्षक शिवनारायण सिंह
2. उप निरीक्षक दीनदयाल वर्मा
3. सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सोनी
4. सहायक उप निरीक्षक राजकुमार दीवान
5. प्रधान आरक्षक क्रमांक 625 नंद कुमार सिंह
6. प्रधान आरक्षक क्रमांक 998 लवण सिंह
7. प्रधान आरक्षक क्रमांक 727 यदुलाल पाटिल।

उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएसपी रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल में चार कर्मी सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की कर्म शिरोमणि पुरस्कार योजना के तहत रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल के चार कार्मिकों को उत्कृष्ट व अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए सम्मानित किया गया। योजना का उद्देश्य नवाचार, संसाधनों के प्रभावी उपयोग, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। महाप्रबंधक (आरएसएम) एनके खरे ने प्रदुमन सिंह, रोहित कुमार साहू, श्रवण कुमार कश्यप और सन्नी दीपक कुल्लू को स्मृति चिह्न व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए।

उनके जीवनसाथियों को प्रशंसा-पत्र और मिठाई कूपन देकर सहयोग का सम्मान भी किया गया। खरे ने कहा कि ऐसे सम्मान सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से सुरक्षा को प्राथमिकता देकर गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यकुशलता के नए मानक बनाने का आग्रह किया।

जलभराव रोकने युद्धस्तर पर अभियान

भिलाई क्षेत्र के वार्डों में खोली जा रही चोक नालियां

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने मानसून के दौरान शहर में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत सभी संवेदनशील वार्डों में नालियों की सफाई, चोक पाइंट खोलने तथा वर्षाजल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश के दौरान कहीं भी पानी का ठहराव न हो और नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

निगम आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं जोन की टीमों ने ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है, जहां पूर्व वर्षों में वर्षाजल के ठहराव की स्थिति निर्मित होती रही है। इन स्थानों पर विशेष रूप से नालियों के चोक पाइंट खोले जा रहे हैं, ताकि वर्षाजल बिना किसी अवरोध के मुख्य नालियों तक पहुंच सके। जहां प्राकृतिक बहाव बाधित है, वहां रेनकट (कच्ची नाली) बनाकर पानी का निकास मुख्य नालियों की ओर कराया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में सफाई अमला लगातार फील्ड में मौजूद रहकर नालियों में जमा गाद, प्लास्टिक, कचरा एवं अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य कर रहा है। अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त श्रमिक एवं संसाधन भी लगाए जा रहे हैं।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। जिन क्षेत्रों में पानी भरने की संभावना हो, वहां पहले से ही आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर समस्या का निराकरण किया जाए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल नालियों की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर में ऐसी प्रभावी जल निकासी व्यवस्था विकसित करना है जिससे मानसून के दौरान सड़कें जलमग्न न हों, यातायात प्रभावित न हो और आम नागरिकों का दैनिक जीवन सुचारु रूप से चलता रहे।

ग्रामीणों की मांगें हुई पूरी थनौद के किसानों ने जताया आभार

दुर्ग। भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत ग्राम थनौद से जुड़ी लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांगों का समाधान होने पर ग्रामीणों और किसानों ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर अभिजीत सिंह का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण कृषकों ने बताया कि आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अंडरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने जनदर्शन में मांग की जा रही थी, जिसे स्वीकृति प्रदान किया गया। इसके अलावा शिवनाथ नदी-नाले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पुल (ब्रिज) की लंबाई बढ़ाने की मांग भी पूरी की गई है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव और बाढ़ का प्रभाव कम होगा तथा लोगों और किसानों को आवागमन में राहत मिलेगी।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रोशन हुआ भविष्य, अब बिजली बिल हुआ शून्य

रायपुर। कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत समनापुर के निवासी रोशेलाला पाटिल के लिए बढ़ता बिजली बिल हर महीने चिंता का कारण बनता था। उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग पंद्रह सौ से 2 हजार रुपये तक आता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद पिछले छह महीनों से उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है। रोशेलाला पाटिल बताते हैं कि पहले बिजली का सीमित उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब वे पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी और मोटर पंप सहित सभी विद्युत उपकरणों का बिना किसी चिंता के उपयोग कर रहे हैं। उनका घर अब केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन करने वाला घर भी बन गया है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिली है, जबकि राज्य सरकार से 35 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता भी स्वीकृत हुई है। सरकार की इस सहायता से सोलर प्लांट लगवाना उनके लिए आसान हो गया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026 और नियामकीय सुधारों पर चर्चा

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (डीरिग्युलेशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2026' के प्रारूप तथा निवेश संवर्धन, डिजिटल सुविधा और व्यवस्थित नियामकीय सुधारों के लिए तैयार किए गए परिचालन ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने तथा नागरिकों को शासकीय सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उपायों की समीक्षा की गई। परिचालन ढांचे के अंतर्गत 'इन्वेस्ट छत्तीसगढ़' के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था , पांच प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित कार्यप्रणाली, 180 शासकीय सेवाओं का सरलीकरण तथा नौ विभागों को इस व्यवस्था से जोड़ने संबंधी प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया।

मड़कम देवा ने झींगा पालन से लिखी सफलता की नई कहानी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और उद्यानिकी जैसे आयवर्धक व्यवसायों को लगातार बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ के सुकमा जिले के दुब्बाटोटा गांव के किसान मड़कम देवा इसकी प्रेरक मिसाल बनकर उभरे हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने झींगा और मछली पालन शुरू किया और आज आत्मनिर्भर बन चुके हैं। मड़कम देवा ने मत्स्य पालन विभाग की योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए 7.20 लाख रूपए का ऋण प्राप्त किया, जिसमें 4.20 लाख रुपये का अनुदान शामिल था। इसके अलावा क्रेड़ा विभाग से अनुदान पर सोलर पंप मिलने से उन्हें 24 घंटे सिंचाई और तालाब में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। इससे उनका व्यवसाय शुरू करना आसान हो गया। मड़कम देवा ने कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से आधुनिक मत्स्य पालन का प्रशिक्षण लिया।

संकट की घड़ी में बना सहाराः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से मिला दो लाख रुपये का आर्थिक संबल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर वनांचल तक पहुंच रहा है। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने एक जरूरतमंद परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहारा देकर संवेदनशील शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

दुख की घड़ी में मिला आर्थिक संबल

सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम आरलमपल्ली की दुर्गा स्व-सहायता समूह से जुड़ी बिहान की दीदी दुधी सन्नी का 8 अप्रैल 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में बिहान योजना की टीम ने तुरंत बीमा दावा तैयार कर भारतीय स्टेट बैंक की दोरनापाल शाखा को भेजा। बैंक ने भी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता से पूरी कीं। संयुक्त प्रयासों का परिणाम यह रहा कि मृतिका के पति एवं नामिनी दुधी सोमा के बैंक खाते में 27 मई 2026 को मात्र दो महीने के भीतर 2 लाख रुपये की बीमा दावा राशि जमा हो गई। यह सहायता राशि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा नायक द्वारा हितग्राही को प्रदान की गई।

टीमवर्क से मिली समय पर राहत

इस कार्य में भारतीय स्टेट बैंक दोरनापाल के शाखा प्रबंधक आनंद सिंह, बिहान की पीआरपी श्रीमती रूकमणी कर्मा तथा एफएलसीआरपी कुमारी शालिनी ओडला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी के समन्वित प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले परिवार को बिना अनावश्यक विलंब के आर्थिक सहायता मिल सकी।

गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बन रही योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। परिवार के कमाने वाले सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में मिलने वाली बीमा राशि संकट की घड़ी में बड़ा सहारा साबित होती है। दुधी सन्नी के परिवार की यह कहानी बताती है कि जब शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचता है, तो वह न केवल आर्थिक सहायता देता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में परिवार को नया संबल और विश्वास भी प्रदान करता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र से राष्ट्रीय पहचान तकः अरनपुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मिला एनक्यूएएस प्रमाणन

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने किया सम्मानित, वन मंत्री केदार कश्यप ने दी बधाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाला दंतेवाड़ा जिले का अरनपुर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, अरनपुर को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) प्रमाणन प्रदान किया गया है।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी (स्वास्थ्य) जयंत नाहटा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दूरस्थ क्षेत्र स्थित अरनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अरनपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान दंतेवाड़ा जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्वास्थ्य विभाग भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते हुए आम नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, दवाइयों की उपलब्धता, स्वच्छता, मरीजों की संतुष्टि, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्टाफ की कार्यकुशलता और उपचार व्यवस्था सहित विभिन्न मानकों का मूल्यांकन किया गया। सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य केंद्र को यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा और अधिक बल

एनक्यूएएस प्रमाणन के बाद स्वास्थ्य केंद्र को केंद्र सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रखरखाव तथा मरीजों को और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को भी मिलेगा लाभ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि जिले में एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की गई। जिला नोडल अधिकारी (क्वालिटी) श्री प्रतीक सोनी तथा जिला क्वालिटी सलाहकार श्री अंकित सिंह के मार्गदर्शन में सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की गईं। उन्होंने बताया कि अब जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को भी एनक्यूएएस प्रमाणन दिलाने के लिए इसी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं।

यह उपलब्धि न केवल अरनपुर, बल्कि पूरे दंतेवाड़ा जिले के लिए गर्व का विषय है और यह दर्शाती है कि दूरस्थ एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जल संरक्षण से समृद्धि की नई धाराः चन्द्रगढ़ का चेक डेम बना किसानों की खुशहाली का आधार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जल संरक्षण के प्रभावी प्रयास किस प्रकार ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि का आधार बन सकते हैं, इसका प्रेरक उदाहरण बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत चन्द्रगढ़ में देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कोरोना नाले पर निर्मित चेक डेम ने गांव की कृषि व्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में निर्मित इस संरचना से क्षेत्र में जल संचयन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को अब वर्षभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा है।

चेक डेम से सीधे तौर पर 10 किसानों की लगभग 3.325 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है, वहीं ग्राम के 20 से 25 अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है। जल उपलब्धता बढ़ने से किसानों ने परंपरागत खेती के साथ मक्का, धान, सरसों तथा विभिन्न सब्जियों की खेती को अपनाया है, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

सिंचाई सुविधा मिलने से खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों में बहुफसली खेती के प्रति रुचि भी बढ़ी है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

चन्द्रगढ़ का यह चेक डेम केवल जल संरक्षण की एक संरचना नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि, टिकाऊ कृषि और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। यह पहल दर्शाती है कि योजनाबद्ध जल संरक्षण प्रयास गांवों में आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास की मजबूत नींव रख सकते हैं।

डिजिटल व्यवस्था से आसान हुई सरकारी सेवाओं तक पहुंच

'सेवा सेतु' ने दी राहत, कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना समय पर मिला आय प्रमाण-पत्र

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शासन की जनहितकारी पहल 'सेवा सेतु' आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की सहज, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल माध्यम से संचालित इस व्यवस्था ने वर्षों से चली आ रही अनावश्यक भागदौड़ और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया है। अब नागरिकों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

कोरबा के कटघोरा तहसील के ग्राम राल निवासी रामेश्वर कंवर को अपने पुत्र हिमाचल सिंह एवं पुत्री देवांशी कंवर के लिए आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर पटवारी से सत्यापन कराया तथा सुतर्रा स्थित लोक सेवा केंद्र के माध्यम से 'सेवा सेतु' पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित हुई और उन्हें किसी भी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके दोनों बच्चों के आय प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए। रामेश्वर कंवर ने बताया कि 'सेवा सेतु' के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही।

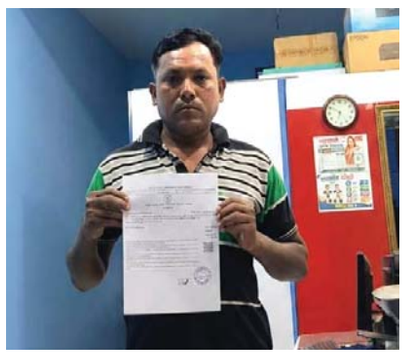

उन्हें समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जिससे उनके समय और संसाधनों दोनों की बचत हुई। उन्होंने कहा कि 'सेवा सेतु' जैसी डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है तथा शासन की सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो रहा है। 'सेवा सेतु' के माध्यम से शासन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पहल सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है।

वीबी जीरामजी प्रदेश में लागू, पहले ही दिन श्रमिकों को मिली सौगात

वीबी जीरामजी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर 261 से बढ़कर हुई 300 रुपए प्रतिदिन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वीबी जी राम जी के लागू होने के पहले दिन ही श्रमिकों को बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। जहां भारत सरकार द्वारा विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके तहत मजदूरी दर में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अभूतपूर्व है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लिए संशोधित मजदूरी दर निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए अकुशल हस्त कार्य हेतु मजदूरी दर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा वीबी जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है । आज से वीबी जीरामजी पूरे देश के साथ राज्य में भी लागू हो गयी है। जिसका पूरे राज्य में श्रमिकों द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। कार्य स्थलों पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के हर ग्राम में वीबी जी राम जी के आगमन को एक उत्सव की तरह मनाते सभी को योजना की जानकारी दी जा रही है। 2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, वहीं प्रदेश में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे।

अब 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था प्राप्त होगी। वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका पर जोर दिया गया है।

अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, जनभागीदारी और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस, रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण सहित नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कचरे के पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक प्रबंधन में नागरिकों, स्थानीय निकायों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए इसे जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

क्षेत्रीय अधिकारी पी.के. रबड़े ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका उद्देश्य कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का सफल मॉडल विकसित किया है। साथ ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सीमेंट संयंत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से तैयार आर.डी.एफ (त्यनिम क्मतपअमक थ्नमस) का ईंधन के रूप में उपयोग कर कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामूहिक प्रयासों से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को जीरो वेस्ट स्टेट बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला में राज्य सलाहकार मोनिका सिंह एवं पुरुषोत्तम पंडा (स्वच्छ भारत मिशन), कार्यपालन अभियंता योगेश कुमार कडू, मुख्य रसायनज्ञ श्रीमती नीलिमा सोनकर तथा सहायक अभियंता प्रवीण कुमार नाग ने पॉवरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, स्रोत स्तर पर पृथक्करण, प्रसंस्करण तथा व्यावहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि, बल्क वेस्ट जेनरेटर, ईको क्लब समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी-कर्मचारी सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यशाला का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था।

आईने के सामने खुद को देख रो पड़ती थीं अविका गौर

13 किलो वजन घटाकर किया असली ट्रांसफॉर्मेशन

अभिनेत्री अविका गौर ने टीवी स्क्रीन पर मासूम आनंदी बनकर घर-घर में पहचान बनाई, लेकिन एक समय उन्हें अपनी जिंदगी में खुद से लड़ाई लडनी पड़ी थी। वह आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं। मुंबई में जन्मीं अविका गौर ने बहुत छोटी उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 2007 में उन्होंने श२१श.कोई है से छोटे रोल के जरिए टीवी डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2008 में आए शो बालिका वधू से मिली।

इस शो में उन्होंने छोटी आनंदी का किरदार निभाया, जो एक बाल विवाह की कहानी पर आधारित था। उनके मासूम अभिनय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और वह बहुत जल्दी घर-घर में पहचानी जाने लगीं। इसके बाद अविका ने ससुराल सिमर का में रोली का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा लड़की की भूमिका निभाई। यह रोल उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में किया था। इस शो ने भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। इसमें उनकी और अभिनेता मनीष रायसिंघन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

टेलीविजन की सफलता के बाद अविका ने फिल्मों की ओर रुख किया। उन्होंने 2009 में मॉर्निंग वॉक और पाठशाला जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2013 में तेलुगु फिल्म उय्याला जम्पला से उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें एसआईआईएमए अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई।

एक समय ऐसा भी आया जब अविका अपने शरीर और आत्मविश्वास को लेकर संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने खुद बताया था कि एक समय वह आईने में खुद को देखकर टूट गई थीं और रो पड़ी थीं। उन्हें अपना बढ़ा हुआ वजन और बदलता लुक स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। इस मानसिक संघर्ष ने उनकी सोच को बदल दिया।

इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, नियमित वर्कआउट शुरू किया और अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। इस बदलाव के जरिए उन्होंने करीब 13 किलो वजन कम किया और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया। उन्होंने कहा था कि पहली बार उन्होंने खुद को वैसे स्वीकार करना सीखा जैसा वह हैं।

इसी बीच अविका ने रियलिटी शोज जैसे खतरों के खिलाड़ी 9 और दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया। उन्होंने 1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें वह लीड रोल में नजर आईं। अपने करियर में अविका गौर ने कई अवॉर्ड्स हासिल किए, जिनमें आईटीए सर्टिफिकेट और एसआईआईएमए अवॉर्ड शामिल हैं।

कृति सेनन ने कबीर बहिया के साथ रोमांटिक तस्वीर शेयर कर मचाई हलचल

कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखे पलों को साझा किया है। उन्होंने कबीर बहिया के साथ प्यारी तस्वीर साझा करके उनके साथ ब्रेकअप की अफवाहों को खारिज कर दिया है।

अभिनेत्री कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर चल रही अपने और बिजनेसमैन कबीर बहिया के ब्रेकअप की अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर साल 2026 के शुरुआती छह महीनों के कुछ अनदेखे पलों की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें कबीर बहिया के साथ उनकी रोमांटिक तस्वीर भी शामिल है।

कृति ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरों को साझा किया है। इन तस्वीरों में उनके साथ दो तस्वीरों में कबीर भी नजर आ रहे हैं। अपनी इन तस्वीरों के साथ कृति ने कैप्शन में लिखा, 'कुछ ऐसे पल जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं आए'।

एक तस्वीर में कृति और कबीर एक साथ लाइव परफॉर्मेंस का आनंद लेते और एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही फैंस बेहद खुश हैं क्योंकि इससे यह साफ हो गया है कि दोनों अब भी साथ हैं।

अफवाह की वजह

कुछ दिनों पहले कबीर बहिया की एक महिला के साथ तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद इंटरनेट पर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि कृति और कबीर का ब्रेकअप हो गया है। कबीर के करीबी सूत्रों ने साफ किया कि वायरल तस्वीर में दिख रही महिला कबीर की पारिवारिक दोस्त है, जिसे वे अपनी बहन जैसा मानते हैं। लोगों ने इसे गलत समझा और झूठी अफवाहें फैला दीं।

कृति सेनन का वर्कफ्रंट

कृति सेनन की हालिया फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है। अब तक फिल्म ने 85 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी हैं। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कृति आने वाली फिल्म 'डॉन 3' में भी नजर आ सकती हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

बटवारा 1947 टीजर रिलीज, नफरत के दौर में उम्मीद की आवाज बना एक नायक

बंटवारा 1947 इस साल की सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। अपने शानदार मोशन पोस्टर और किरदारों के दमदार पोस्टर्स के रिलीज होने के बाद से ही, इस फिल्म ने हर तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। यह एक ऐसी कहानी के लिए उत्सुकता बढ़ा रही है जो हिम्मत, बलिदान और कभी न टूटने वाले इंसानी जज्बे से जुड़ी है।

बंटवारा 1947 का यह दिलचस्प और इंटेंस टीजर दर्शकों को इतिहास के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक में ले जाता है, भारत की आजादी और वो दर्दनाक बंटवारा जिसने एक देश को बांट दिया और हमेशा के लिए करोड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया। दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर से भरा यह टीजर इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे चैप्टर के दौरान उम्मीद और लचीलेपन के जज्बे को दिखाता है। हमारी इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा हीरो है जो डर और नफरत से ऊपर उठकर असाधारण बहादुरी की मिसाल बनता है।

बंटवारा 1947 में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे शानदार कलाकारों की फौज है। यह फिल्म करीब तीन दशकों के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बहुप्रतीक्षित वापसी को भी दिखाती है।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी बंटवारा 1947 को नेशनल अवार्ड विनर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। इसका म्यूजिक ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं। आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म पार्टीशन डे के मौके पर 14 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हरे या काले, कौन से अंगूर हैं ज्यादा पौष्टिक? आयुर्वेद से जानें दोनों के औषधीय लाभ

अंगूर बहुतायत मात्रा में आसानी से मिल जाते हैं। अंगूर केवल स्वादिष्ट फल नहीं है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं। अंगूर को आयुर्वेद में द्राक्षा कहा जाता है, जो शरीर को शीतलता और पोषण दोनों देता है।

हरा अंगूर शरीर में जल-संतुलन और पित्त शमन में सहायक माना जाता है, जबकि काला अंगूर रक्त को पोषण देने और थकान से उबरने में उपयोगी बताया गया है। वहीं विज्ञान ने भी अंगूर को विटामिन से भरपूर पाया है, जो मस्तिष्क से लेकर हृदय तक के लिए लाभकारी है। यह कोशिकाओं की रक्षा करता है और शरीर में ऊर्जा का प्रसार भी तेजी से करता है।

पहले विस्तार में बात करते हैं हरे अंगूर की। हरे अंगूर स्वाद में मधुर और पाचन में हल्के होते हैं। हरे अंगूर में पित्त को शांत करने की क्षमता होती है। यह शरीर में गर्मियों में होने वाले निर्जलीकरण से बचाते हैं और पेट में होने वाली जलन को भी कम करते हैं। अगर गर्मी में लू लगने का खतरा लगता है, तब भी अंगूर का सेवन गर्म हवा से सुरक्षा प्रदान करता है।

वहीं काले अंगूर हरे अंगूर की तुलना में ज्यादा पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। काले अंगूर का सेवन शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है और बल भी प्रदान करता है। काले अंगूर स्किन को साफ करने और बालों को चमकदार बनाने में भी सहायक हैं। काले अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो शरीर की आंतरिक कमजोरी और थकावट को भी दूर करते हैं और विटामिन सी और ई मिलकर बालों और स्किन को निखारने का काम करते हैं।

अब सवाल है कि अंगूर खाने का सही समय क्या है। वैसे आमतौर पर फल को कभी भी खा लिया जाता है, जो गलत है। अंगूर का सेवन सुबह और दोपहर में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंगूर का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। विटामिन सी होने की वजह से ये पेट में जलन पैदा कर सकते हैं।

क्या आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं? जानिए इसके कारण

कई लोग सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अलार्म बजने के बाद भी उठने के लिए जूझते रहते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से एक हैं तो इसका कारण आपका शरीर और मन हो सकता है। यह एक अच्छी आदत है और इससे आपका दिन बेहतर ढंग से शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं कि सुबह अलार्म से पहले उठने के पीछे का कारण क्या है।

शरीर की आंतरिक घड़ी

आपके शरीर की अपनी एक आंतरिक घड़ी होती है, जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। यह घड़ी आपको बताती है कि कब सोना है और कब उठना है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो आपका शरीर इस समय को पहचान लेता है और खुद-ब-खुद उसी समय पर जागने की आदत डाल लेता है। इससे आप बिना अलार्म के भी आसानी से उठ जाते हैं।

सोने की आदत बनाना

अगर आप नियमित रूप से एक ही समय पर सोते हैं तो आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे नींद गहरी होती है और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। इसके अलावा एक निश्चित समय पर सोने से आपका शरीर आराम महसूस करता है और सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह आदत आपके शरीर को जैविक घड़ी के अनुसार काम करने में मदद करती है, जिससे आप बिना अलार्म के भी जल्दी उठ जाते हैं।

प्राकृतिक रोशनी का महत्व

सुबह की पहली किरण आपके शरीर को बताती है कि दिन शुरू हो गया है। अगर आप अपने कमरे में सुबह की रोशनी आने दें तो आपका शरीर खुद-ब-खुद जाग जाएगा। इसके लिए आप पर्दे हटाकर खिड़की खोल सकते हैं या फिर प्राकृतिक रोशनी आने वाली जगह पर सोने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपका शरीर जैविक घड़ी के अनुसार काम करेगा और आप बिना अलार्म के भी जल्दी उठ जाएंगे।

मानसिक तैयारी

अगर आप रात को सोने से पहले यह सोच लें कि सुबह उठकर क्या करना है तो आपका मन पहले से ही तैयार हो जाता है। इससे आप सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं और आलस्य नहीं आता। इसके अलावा आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान या सांस लेने के अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और उठते ही सक्रिय हो जाएंगे।

स्वस्थ जीवनशैली

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से भी सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको संतुलित भोजन, नियमित कसरत और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इसके अलावा तनाव मुक्त रहने के लिए योग या ध्यान कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपनी सुबह की दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं और बिना अलार्म के भी जल्दी उठ सकते हैं। रात को जल्दी सोने से भी सुबह जल्दी उठना आसान हो जाता है।

कंगना रनौत की 'लॉक अप 2' में वापसी बनकर आएंगी 'जनता की आवाज'

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जल्द ही लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो 'लॉक अप 2' में वापस नजर आने वाली हैं। लेकिन इस बार वह इस शो में जूरी का हिस्सा बनेंगी।

अभिनेत्री कंगना रनौत इस हफ्ते के आखिर में नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में एक खास मेहमान के रूप में दिखाई देंगी। इस बार वह शो में 'जनता की आवाज' बनकर एंट्री लेंगी।

कंगना बनेंगी 'जनता की आवाज'

शो से पहले कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन के दौरान कंगना मुख्य होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख के साथ जूरी का हिस्सा बनेंगी। कंगना ने कहा कि यह शो सच को स्वीकार करने के बारे में है और यहां हर फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ती है।

इस शो के पिछले सीजन को खुद कंगना ने ही होस्ट किया था, इसलिए उनकी वापसी से फैंस काफी उत्साहित हैं। इस नए सीजन में धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी समेत 15 कंटेस्टेंट्स शामिल हैं।

फिल्म 'क्वीन 2' की शूटिंग हुई पूरी

टीवी शो के अलावा कंगना अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्वीन' के सीक्वल यानी 'क्वीन 2' को लेकर भी चर्चा में हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस फिल्म की मुख्य शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने पूरी टीम के साथ इसका जश्न भी मनाया।

हाल ही में कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं, जो 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म साहस और बलिदान पर आधारित है, जो मुंबई हमलों (26/11) के दौरान अस्पताल के उन गुमनाम कर्मचारियों की सच्ची कहानी को दर्शाती है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 400 से अधिक मरीजों की जान बचाई थी।

खास खबर

आदिवासी हितों के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश : मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, रायपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट, 1996 एवं राज्य के पेसा नियम, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति अथवा पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई, आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधित अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आदिवासियों के हित संबंधित विषयों के समन्वित अध्ययन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग तथा खनिज विभाग के सचिवों को सदस्य बनाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए।

रायपुर में तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का फेरबदल, 9 अधिकारियों के तबादले

रायपुर। रायपुर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए 9 अधिकारियों का तबादला किया है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर कार्यरत नरेंद्र वर्मा को रायपुर का नजूल तहसीलदार बनाया गया है। वहीं राजकुमार साहू को रायपुर से धरसीवा तहसील की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादला सूची के मुताबिक बाबूलाल कुर्रे को धरसीवा से आरंग, सृजन सोनकर को खोरपा (अभनपुर) से खरोरा, विकांत सिंह राठौर को गोबरा नवापारा से मंदिर हसौद तथा चंद्रशेखर मंडई को खरोरा से गोबरा नवापारा पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार गजानंद सिदार को समोदा (आरंग) से खोरपा (अभनपुर), टोमन कुमार को तिल्दा से समोदा (आरंग) तथा अजय कुमार पांडे को सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख से नायब तहसीलदार तिल्दा-नेवरा के पद पर पदस्थ किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पदस्थापन आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा, जबकि अन्य सभी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को राजस्व कार्यों में तेजी लाने, कार्यों के बेहतर समन्वय तथा तहसीलों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर किया आत्मीय स्वागत

न्योता भोज में साथ में किया भोजन, शाला प्रवेशोत्सव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में सेजेस लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित देवकीनंदन दीक्षित सभागार में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, संस्कारवान नागरिक बनने और अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का संदेश दिया।

अतिथियों ने बच्चों के साथ न्योता भोज में शामिल होकर भोजन किया। कार्यक्रम में छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल का वितरण भी किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी और जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भी शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए।

शाला प्रवेशोत्सव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों को नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शाला प्रवेशोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राथमिक पाठशाला की स्मृतियां हमेशा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे संस्कार और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे मन से अध्ययन कर अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। आज स्कूलों में भवन, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सम्मानपूर्वक आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थियों को पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपनी प्रतिभा से पूरे देश में राज्य का गौरव बढ़ाने की अपील की।

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि विद्यालयों का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय शौचालयविहीन, जर्जर या अवैध कब्जे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। विद्यालयों का वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के अनुकूल होना चाहिए।

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बिल्हा शासकीय स्कूल के शिक्षक कलेश्वर साहू को सम्मानित किया गया। उन्होंने दो लाख सीड-बॉल तैयार किए हैं। साहू ने अतिथियों को सीड-बॉल भेंट किए। निःशुल्क शैक्षणिक सहयोग देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने अतिथियों का मन मोह लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप, जिला पंचायत सदस्य मती अंबिका साहू, पूर्व महापौर किशोर राय, नगर निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जायसवाल, दीपक सिंह, मोहित जायसवाल और राजेश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, पालक एवं विद्यार्थी भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद थे।

भानपुरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के भानपुरी में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में दोनों अतिथियों ने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बच्चों को स्कूल बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की गई। वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि शिक्षा एक मजबूत और विकसित समाज की सबसे बड़ी आधारशिला है। राज्य सरकार का उद्देश्य हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने सभी बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकें।

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक का लाभ उठाकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर ग्राम बनियागांव में 1 करोड़ 12 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया। नए भवन से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और सुविधायुक्त वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट टीवी प्रदान किए गए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा सभी बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई।

कार्यक्रम के अंत में वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। शाला प्रवेश उत्सव ने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह का नया संदेश दिया।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा अंतर्गत सेक्टर खिसोरा-34 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एनरोलमेंट माह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ना तथा बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक करना था।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्कूल चलो अभियान के तहत बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया गया। अभिभावकों से बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की गई।

इस अवसर पर छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, मध्याह्न भोजन सहित शासन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं को नियमित अध्ययन, विद्यालय में सतत उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

जनदर्शन में मंत्री राजेश अग्रवाल ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड लखनपुर की ग्राम पंचायत परसोंडी पहुंचकर ग्रामीणजनों से आत्मीय भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने पेयजल, सड़क, विद्युत, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े विषय मंत्री अग्रवाल के समक्ष रखे। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है, जहां आम नागरिक अपनी बात सीधे रख सकता है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास के संकल्प को साकार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री राजेश अग्रवाल के सहज, सरल एवं संवेदनशील व्यवहार की सराहना करते हुए अपनी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनके समाधान के लिए त्वरित पहल करने पर आभार व्यक्त किया।

धान के साथ दलहन-तिलहन की भी करें खेती, मेड़ों में मुनगा लगाएं

मिश्रित खेती अपनाएं किसान - रामविचार नेताम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम कांकेर में किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को धान के साथ दलहन-तिलहन की भी खेती करना चाहिए। उन्होंने कम पानी एवं कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की खेती करने को कहा। इससे पानी की बचत होगी और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। संगोष्ठी में किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा आत्मनिर्भरता दलहन-तिलहन मिशन के अंतर्गत दलहन बीज वितरित किए गए। विधायक आशाराम नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी संगोष्ठी में शामिल हुए।

कृषि मंत्री नेताम ने खेत के मेड़ों में मुनगा का पौधा लगाने, अरहर की खेती करने तथा मिश्रित खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को खेती के साथ-साथ मछलीपालन, मुर्गीपालन और पशुपालन भी करने को कहा। घर-घर में गाय के पालन से घर की जरूरत भी पूरी होगी, अतिरिक्त आमदनी होगी, पोषण मिलेगा और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के अधिकाधिक उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसलिए किसान जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ सीजन में धान की फसल ली थी, वे इस वर्ष खरीफ में धान के बदले अन्य फसल, मक्का या दलहन-तिलहन लगाएंगे, तो शासन द्वारा प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।

कृषि मंत्री नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में लक्ष्मी स्वसहायता समूह द्वारा किए जा रहे मिलेट प्रोसेसिंग कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर कोदो, कुटकी व रागी की प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि मिलेट प्रोसेसिंग से समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह लगभग छह से सात हजार रुपए की आमदनी हो रही है। नेताम ने समूह की आय आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के मेड़ों में चार चिरौंजी के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कड़कनाथ हेचरी के अवलोकन के दौरान कड़कनाथ पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण और चूजों के विक्रय के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से जानकारी ली।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम और विधायक आशाराम नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में नारियल के पौधे का रोपण किया। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव रसागर, कृषि विभाग के संचालक राहुल देव, पशुधन विकास विभाग के संचालक चंद्रकांत वर्मा, मछलीपालन विभाग के संचालक नारायण सिंह नाग, कांकेर जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीरबल साहू, कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. नितिन रस्तोगी, कृषि वैज्ञानिक नरेन्द्र तायड़े और प्रगतिशील कृषकों सहित कृषि, पशुधन विकास तथा मछलीपालन विभाग के अधिकारी भी संगोष्ठी में मौजूद थे।

सेवा सेतु बना आम लोगों का सहारा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच और सुशासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा संचालित सेवा सेतु पहल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो रही है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों को आय, जाति, निवास सहित अन्य आवश्यक शासकीय प्रमाण-पत्र सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। बीजापुर जिले के गंगालूर तहसील अंतर्गत ग्राम गंगालूर निवासी सन्नू हेमला ने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके आवेदन का निराकरण कर उन्हें आय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

मारपीट, अवैध शराब और चाकूबाजी के मामलों में कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौज, अवैध शराब बिक्री और अवैध हथियार रखने के मामलों में पुलिस ने कई प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। गुढ़ियारी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के कब्जे से 17 पाव देशी शराब और 400 रुपये, जबकि दूसरे के पास से 16 पाव देशी शराब और 300 रुपये जब्त किए गए। दोनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने बांधवापारा तालाब के पास कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चाकू जब्त कर उसके खिलाफआर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी मामलों की विवेचना जारी है।

अवैध शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार, मसाला शराब जब्त

दुर्ग। नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिलाई-3 के बिजली नगर मैदान स्थित खंडहर के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। आरोपी ने अपना नाम सुरेश बारिक निवासी लोधीपारा, खुर्सीपार, जिला दुर्ग बताया। थैले से 30 पौवा देशी मसाला शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,000 रुपये बताई गई। बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 331/2026 के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

शराब दुकान से 7 लाख की चोरी का खुलासा

रायपुर। राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र स्थित सरोना की कम्पोजिट विदेशी शराब दुकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आमानाका थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान के 4 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 14 जून 2026 की सुबह शराब दुकान का ताला टूटा मिला। जांच करने पर पता चला कि चोर दुकान का लॉकर ही उखाड़कर ले गए, जिसमें 7,05,580 रुपये की बिक्री राशि रखी थी। इसके अलावा करीब 10,820 रुपये मूल्य की शराब और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोरी कर लिया गया था। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

4 साल से केबल-लोहा चुराने वाले गैंग का खुलासा

रेलवे की पटरी तक उखाड़ी, निर्माणाधीन और सुनसान इलाकों को बनाते थे निशाना, 2 गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नवा रायपुर में पिछले 4 साल से केबल और लोहे के सामानों की चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह चोर रात के अंधेरे में निर्माणाधीन इलाकों में पहुंचकर केबल, रेलिंग, लोहे की छड़, सड़क किनारे लगे रॉड ही नहीं, बल्कि रेलवे लाइन के पास की लोहे की पटरी तक उखाड़ ले जाते थे। पुलिस को आशंका है कि दोनों कई पुराने चोरी के मामलों में भी शामिल रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-24 स्थित सतनाम चौक सहित नवा रायपुर के कई इलाकों से लगातार लोहे के सामान और केबल चोरी होने की शिकायतें मिल रही थीं। 29 जून की रात करीब 2:45 बजे एनआरडीए की पेट्रोलिंग टीम ने दो युवकों को केबल काटते हुए देखा। टीम ने पीछा भी किया, लेकिन दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। मामला राखी थाना इलाके का है।

तकनीकी जांच और निगरानी से पहुंचे आरोपियों तक

ग्रामीण एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देश पर गठित टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और कई दिनों तक संदिग्धों की निगरानी की। जांच के बाद पुलिस ने विजय कुमार ठाकुर और विक्की सवरा को हिरासत में लिया।

पहले दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे पिछले तीन से चार साल से नवा रायपुर के सुनसान और निर्माणाधीन इलाकों में चोरी कर रहे थे।

रेलिंग से लेकर रेलवे पटरी तक बरामद

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई लोहे की छड़, एंगल, रेलिंग, सड़क किनारे लगे रॉड, रेलवे लाइन के पास से चोरी की गई लोहे की पटरी और केबल तार बरामद किए हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि दोनों की संलिप्तता नवा रायपुर में हुई अन्य चोरी की वारदातों में भी रही है या नहीं।

गिरफ्तार आरोपी

विजय कुमार ठाकुर (30), निवासी ग्राम पलोद, थाना मंदिर हसौद, विक्की सवरा (30), मूल निवासी ग्राम पटेवा, थाना अभनपुर। वर्तमान पता- ग्राम पलोद, थाना मंदिर हसौद।

जेल से छूटते ही युवक से 15 हजार लूटे, रास्ता रोककर की मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जेल से छूटने के महज तीन दिन बाद एक बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने आधी रात घर लौट रहे एक युवक का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और जेब में रखे 15,200 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ढिमरापुर निवासी त्रिनाथ सामल (31) जगन्नाथ हरिशचंद्र ज्वेलर्स में सेल्समैन है। वह दुकान के काम से रायपुर गया था और सोमवार रात राजहंस बस से रायगढ़ लौटा। चावला फर्नीचर के पास उतरकर उसने मालिक के घर सामान छोड़ा और रात करीब 12:30 बजे अपने कमरे की ओर जा रहा था।

इसी दौरान ढिमरापुर रोड स्थित आदित्य बाइक दुकान के पास दो युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों ने रुपए की मांग की और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जेब में रखा पर्स छीनकर उसमें मौजूद 15,200 रुपए लेकर फरार हो गए। मारपीट में त्रिनाथ के दोनों हाथों में चोट आई।

पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर दो संदिग्ध युवक नजर आए। उनकी पहचान बापूनगर और रामभाठा क्षेत्र के रहने वाले नीरज टोप्पो (19) और शैलेष मिंज (22) के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रामभाठा मुक्तिधाम के पास से हिरासत में लिया। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई पहचान परेड में पीड़ित ने दोनों की पहचान की। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वारदात के बाद वे झारसुगुड़ा (ओडिशा) घूमने चले गए थे और लूट की अधिकांश रकम खर्च कर चुके हैं। नीरज टोप्पो के खिलाफ कोतवाली थाने में दो चोरी और एक लूट का मामला पहले से दर्ज है। पुलिस के अनुसार नीरज घटना से सिर्फ तीन दिन पहले ही जेल से छूटा था और बाहर आते ही फिर से अपराध कर बैठा। इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : कांकेर में दो बाघ की खाल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में वन विभाग की संयुक्त टीम ने दो बाघों की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के निवासी ब्येश्वर और बाबूराव के रूप में हुई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के निर्देशन में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाघ की खाल के साथ दो आरोपियों को पकड़ा गया गया। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से अनुसूची-1 में शामिल संरक्षित वन्यजीव बाघ की दो खालों

की अवैध तस्करी कर रहे थे। संयुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र, राज्य उड़नदस्ता दल (छत्तीसगढ़ वन विभाग), एंटी पोचिंग यूनिट (यूएसटीआर) तथा स्थानीय वन अमले ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है तथा जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सरकार वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव की अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। वन विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निगरानी और संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

सक्ती में युवती की गोली मारकर हत्या, 9 आरोपी हुए गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले चार दिन पहले युवती की नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले का पुलिस ने घटना के चार दिन बाद खुलासा कर दिया है। युवती की हत्या की सुपारी उसके शादीशुदा प्रेमी ने दी थी। साजिश में उसकी पत्नी भी शामिल रही। इस मामले में पुलिस ने पति-पत्नी सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नगदी भी बरामद की गई है।

मामले का खुलासा करते हुए सक्ती पुलिस ने बताया कि 26 जून को ग्राम जोंगरा निवासी पूर्णिमा चौहान उर्फ पूनम की दो नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से नगर में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी रामगोपाल गर्ग और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने चार दिनों तक मोबाइल टावर डंप, कॉल डिटेल रिकॉर्ड,

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया।

जांच में सामने आया कि मृतका पूर्णिमा चौहान के रायगढ़ जिले के देल्हारी निवासी मुरलीशंकर चौहान के साथ प्रेम संबंध थे। इस संबंध को लेकर मुरलीशंकर और उसकी पत्नी चम्पा चौहान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, बाद में मुरलीशंकर ने पत्नी के कहने पर पूर्णिमा से दूरी बना ली, लेकिन पूर्णिमा लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर मुरलीशंकर और उसकी पत्नी चम्पा ने पूर्णिमा की हत्या की साजिश रची और 4 लाख रुपये की सुपारी देकर राजेन्द्र महंत से हत्या कराने का सौदा किया।

पुलिस के अनुसार, राजेन्द्र महंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। घटना वाले दिन गौरीशंकर सिदार और सुनील महंत मोटरसाइकिल से जोंगरा पहुंचे, जहां गौरीशंकर ने पिस्तौल से पूर्णिमा पर तीन गोलियां दाग दीं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में सुपारी की तय रकम में से 2 लाख रुपये आरोपियों को दिए गए। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने राजेन्द्र महंत को जमशेदपुर (झारखंड), जबकि गौरीशंकर सिदार और सुनील महंत को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया।

इसके बाद अन्य आरोपियों को छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों से पकड़ लिया गया। सभी आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और सुपारी की राशि में से बची नगदी बरामद की है। सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

ग्रामीण बैंक का ताला काटकर घुसा नकाबपोश चोर, पुलिस जांच में जुटी

श्रीकंचनपथ न्यूज

जांजगीर-चांपा। बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम जर्वे स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई। नकाबपोश चोर मुख्य गेट का ताला काटकर बैंक में घुसा और करीब 20 हजार रुपये कीमत का कंप्यूटर सेट चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। एसडीओपी प्रदीप सोरी के अनुसार, रात करीब 3:07 बजे मंकी कैप पहने एक युवक बैंक पहुंचा। आशंका है कि उसने लोहे की रॉड या आरी से मुख्य गेट का ताला काटा और अंदर दाखिल हुआ। बैंक में प्रवेश करते ही उसने

सबसे पहले लाइट बंद कर दी, ताकि उसकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। सूचना मिलते ही बलौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक सबूत एकत्र किए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

रेत की अवैध तस्करी पर वन विभाग का बड़ा प्रहार, 12 ट्रैक्टर जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने रेत की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से लदे 12 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बैहामुड़ा के पास स्थित कुरकुट नदी से लंबे समय से अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। तस्करों ने वन क्षेत्र के भीतर घने जंगल से होकर एक गुप्त रास्ता तैयार कर लिया था, जिससे वे मुख्य सड़क और जांच चौकियों से बचते हुए रेत का परिवहन कर रहे थे।

सूचना मिलते ही वनमंडलाधिकारी अरविंद पी. एम. के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र

अधिकारी विक्रांत कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। वन अमले ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी कर बिना वैध अनुमति और बिना परिवहन पास के रेत का परिवहन कर रहे 12 ट्रैक्टरों को मौके पर ही जब्त कर लिया।

वन अपराध का प्रकरण दर्ज, होगी सख्त कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को देखकर कई तस्कर मौके से भाग निकले, लेकिन विभाग ने रेत से लदे सभी ट्रैक्टर अपने कब्जे में ले लिए। जब्त वाहनों को घरघोड़ा वन परिक्षेत्र कार्यालय लाकर आवश्यक जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वन विभाग ने इस मामले में भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन संपदा के संरक्षण के लिए अभियान रहेगा जारी

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन, रेत तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वन संपदा की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग की इस प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय रेत तस्करों में हड़कंप का माहौल है।

1.56 लाख का सामान चुराने वाला गिरफ्तार

राजनांदगांव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल टीम ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत टाटा-इतवारी एक्सप्रेस के एसी कोच में हुई 1.56 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया। टीम ने 24 घंटे के भीतर हिस्ट्रीशीटर आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी गया पूरा सामान बरामद हुआ। आरोपी को जब्त सामान समेत जीआरपी डोंगरगढ़ के हवाले कर दिया गया।

घटना 30 जून की है जब गाड़ी संख्या 18109 टाटा-इतवारी एक्सप्रेस के एसी कोच बी-2 में यात्रा कर रहे यात्री का लैपटॉप बैग चोरी हुआ। बैग में लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, माउस, चार्जर, हार्ड डिस्क रखी थी। पीड़ित की शिकायत के बाद आरपीएफ ने विशेष टीम बनाई।

मंडल सुरक्षा आयुक्त चेतन डी.

जिचकार ने बताया डोंगरगढ़ पोस्ट, सीआईबी भिलाई, अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए, डोजियर का विश्लेषण किया, मुखबिर तंत्र लगाया। टीम ने संदिग्धों की पहचान की। जांच में आरोपी के रायपुर में होने की सूचना मिली। टीम ने महोबा बाजार, आमानाका इलाके में दबिश दी। विक्की सहानी, उम्र 22 साल को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1.56 लाख रुपए का पूरा चोरी का सामान मिला। शिकायतकर्ता से सामान की पहचान कराई गई।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शेख मुश्ताक अहमद पिता मुमताज अहमद निवासी वार्ड नं.-09. प्लाट नं.-07. सड़क नं.-7. शिवाजी नगर, हनफी मस्जिद के पीछे, कोहका भिलाई. तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023 यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम मुश्ताक अहमद पिता मुमताज अहमद रख लिया हूं।

अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजो में मेरे नये नाम मुश्ताक अहमद पिता मुमताज अहमद से ही जाना पहचाना जावे।

मुश्ताक अहमद
वार्ड नं.-09, प्लाट नं.-07, सड़क नं.-7, शिवाजी नगर, हन्फी मस्जिद के पीछे,कोहका भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, SHEIKH MUSTAQ AHMAD S/O MUMTAZ AHMED Resident of ward no.-09, plot no.- 07, street no.-07, shivaji nagar, Behind Hanfi Masjid kohka bhilai Tahsil and Dist Durg (C.G.) 490023 have changed my old Name SHEIKH MUSTAQ AHMED S/O MUMTAZ AHMED. So in future I should be recognized by my New Name that is MUSTAQ AHMED S/O MUMTAZ AHMED, in all Government and other documents.

MUSTAQ AHMED
ward no.-09, plot no.-07, street no.-07, shivaji nagar, Behind Hanfi Masjid kohka bhilai Tahsil and Dist Durg (C.G.) 490023

जमीन विवाद: दो पक्षों में हुई मारपीट, 6 आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव। मोहारा चौकी क्षेत्र के ग्राम बनबोड़ में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। मारपीट की घटना मंगलवार सुबह 8 बजे हुई थी। दो पक्षों के बीच जमीन बंटवारे और सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा है।

एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना में 5 लोगों को चोंटे आई हैं। पुलिस ने शिकायत के बाद आशाराम छेदैया, गनपत छेदैया, धुरसिंग छेदैया, राम्हु छेदैया, रूकुम छेदैया , गुहरी उर्फ हरी छेदैया को गिरफ्तार किया है।

एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री

शासन-प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए एआई आधारित व्यवस्था होगी विकसित

मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारतनेट फेज-3, सेवा सेतु और डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की समीक्षा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास एवं विस्तार, मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई-प्रगति पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम), सेंटर ऑफएक्सीलेंस, डेटा लैब्स तथा विभिन्न डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने तथा तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है, बल्कि प्रदेश के लोगों को एआई के लिए तैयार करना, व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आय में वृद्धि करना तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में एआई के व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य में मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में प्रस्तुत विजन दस्तावेज में बताया गया कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में एआई सीख सके, सरकार तकनीक आधारित भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे और उद्योगों तथा व्यवसायों को नई गति मिले। इस मिशन के अंतर्गत पांच प्रमुख स्तंभों - एआई कौशल विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप, जागरूकता एवं आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई तथा शासन में एआई के उपयोग - पर कार्य किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, एआई एवं रोबोटिक्स क्लब तथा हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में एआई सर्टिफिक्केशन कार्यक्रम, छात्र परियोजनाओं के लिए अनुदान, आईटीआई में एआई लैब तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई आधारित स्टार्टअप, डेटा सेट तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा, सीड फंडिंग तथा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की भी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

बैठक में सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई उपयोग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर एआई नीति तैयार की जाएगी, जिसमें डेटा सुरक्षा, नागरिकों की निजता का संरक्षण, नियमित तकनीकी ऑडिट तथा केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कानून के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शासन में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, प्रत्येक विभाग का अलग रोडमैप तैयार होगा, एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी एआई पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और समावेशी बन सकें।

बैठक में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले ढाई वर्षों में डीबीएन वित्तपोषित लगभग एक हजार मोबाइल टॉवर स्थापित कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त 577 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 406 टावरों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 171 प्रकरणों का निराकरण आगामी एक माह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भारतनेट फेज-3 की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 4,114 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आईपी-एमपीएलएस आधारित एकीकृत नेटवर्क विकसित किया जाएगा तथा गांवों तक एफ्टीटीएच सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो सकें और डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में राज्य के 36 विभागों की 520 सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें 111 होस्टेड तथा 409 रीडायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। प्रदेशभर में संचालित 16 हजार 726 सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु के माध्यम से 39.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37.52 लाख आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए 94.3 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेवा सेतु में क्यूआर आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण, डिजिलॉकर एकीकरण, ट्रेजरी एवं ई-चालान प्रणाली तथा डीबीटी आधारित भुगतान जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे सेवाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बैठक में नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स, सुरक्षा संचालन केंद्र, जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली तथा डिजिटल निगरानी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इन पहलों से प्रदेश में आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र को नई गति मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा हजारों युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रभात मलिक , सुशासन तथा अभिसरण विभाग के संयुक्त एवं चिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के संकल्प से कुनकुरी में आकार ले रहा आधुनिक नालंदा परिसर

250 सीटर अत्याधुनिक अध्ययन केंद्र से युवाओं को मिलेगी महानगरों जैसी सुविधा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित सलियाटोली में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से 250 सीटर सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह परिसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक आधारित और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री साय ने 21 जून 2025 को इस परियोजना का भूमिपूजन किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर विकसित किए जा रहे हैं। जशपुर जिले में जिला मुख्यालय जशपुर और कुनकुरी के सलियाटोली में

ऐसे आधुनिक परिसर बनाए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को विशाल पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन और तकनीकी सुविधाओं से युक्त अध्ययन वातावरण मिलेगा। यह परिसर विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा।

'डिजिटल लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रबंधन प्रणाली': नालंदा परिसर की लाइब्रेरी में 50 हजार से अधिक पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसके साथ डिजिटल लाइब्रेरी, हाई-स्पीड वाई-फाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष पुस्तकें तथा ई-लर्निंग संसाधनों की सुविधा भी रहेगी। परिसर में आरएफआईडी आधारित प्रवेश प्रणाली, बायोमेट्रिक पहचान, आरएफआईडी से पुस्तकों की ट्रैकिंग तथा आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित पुस्तक प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। नालंदा परिसर जशपुर जिले के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही महानगरों के समान आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की बेहतर तैयारी का सशक्त केंद्र बनेगा।

'आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर'

नालंदा परिसर में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण के बीच विकसित ऑक्सी रीडिंग जोन में भी अध्ययन कर सकेंगे। पर्यावरण अनुकूल के साथ विकसित किया जा रहा है, ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन तथा 50 से अधिक देशी पौधों का रोपण किया जाएगा।

ज्ञान के साथ स्वास्थ्य और नवाचार पर भी रहेगा फोकस

परिसर में विद्यार्थियों की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यूथ टावर, स्पोर्ट्स कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम और हेल्थ जोन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे स्वायत्त एवं स्ववित्तपोषित संचालन मॉडल पर विकसित किया जा रहा है।

रायपुर में होगा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन और सहकार संकल्प दौड़ का भव्य आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 3 और 4 जुलाई को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकार संकल्प दौड़ का भव्य आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री केदार कश्यप करेंगे।

इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त करना तथा सहकार से समृद्धि के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है। सम्मेलन में प्रदेशभर से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव, तेलीबांधा में सहकार संकल्प दौड़ आयोजित की जाएगी। प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सहकारिता के संदेश को आमजन तक पहुंचाना है। 3 और 4 जुलाई को सुबह 11 बजे से कृषि मंडपम ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में सहकारी नीतियों, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में अपेक्स बैंक, राज्य सहकारी संघ, मार्कफेड, लघु वनोपज सहकारी संघ, हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम सहित विभिन्न जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष, सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि अपनी सहभागिता देंगे।

सहकार से समृद्धि का मिलेगा संदेश

सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक ने प्रदेश के किसानों, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, युवाओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया है। यह आयोजन सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, किसान सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच, वार्षिक आयोजनों के लिए कलाकारों से आवेदन आमंत्रित

15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन, शास्त्रीय संगीत, लोककला, नाट्य एवं वाद्ययंत्र प्रस्तुतियों के लिए होगा चयन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी। संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।

विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भरथरी, पंडवानी, ढोलामारू, लोरिकचंदा, नाचा, गम्मत, सुआ, करमा, पंथी, बांसगीत, देवारगीत, ददरिया, जसगीत, संस्कार गायन सहित अन्य पारंपरिक लोकविधाओं में दक्ष कलाकार आवेदन कर सकते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की लोक-सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना है। सांस्कृतिक दलों का चिन्हारी पंजीकरण होना आवश्यक है।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर संभाग की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बुधवार को बस्तर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्जीवित करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने प्राथमिक स्तर पर गणित, हिंदी और अंग्रेजी की मजबूत आधारशिला तैयार करने के लिए कैलेंडरवार, शालावार एवं

विषयवार समय-सारणी के अनुसार पढ़ाई कराने तथा नियमित रिवीजन टेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक ऋतुराज रघुवंशी, कलेक्टर आकाश छिकारा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, संभागीय संयुक्त संचालक एच.आर. सोम सहित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी, बीईओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान आधार बेस ऐप के माध्यम से कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति तथा वीएसके ऐप में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली गई। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा नेटवर्क विहीन स्कूलों की सूची कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने अन्य विभागों में पदस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर वापस भेजने संबंधी निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की।

यादव ने बसाहटवार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, नए विद्यालयों की आवश्यकता, बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना, बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए पोटा केबिनों में अंतरजिला विद्यार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के आधार पर विषयवार यूनिट टेस्ट एवं तिमाही परीक्षाएं आयोजित करने तथा कमजोर विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए।

बैठक में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, रिक्त एवं युक्तियुक्तकरण किए गए पदों, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की कार्ययोजना एवं गैप एनालिसिस की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 10 करोड़ के कार्यों का किया भूमिपूजन

उप मुख्यमंत्री ने मुक्तिधाम के लिए 50 लाख और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ की घोषणा की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के मंगला स्थित माता चौरा में लगभग 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें क्षेत्र के विकास को गति देने वाले कई कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से मंगला सहित आसपास के क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

विधायक सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, महापौर पूजा विधानी और जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विकास को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से विकास कार्यों को गति मिली है। अब केवल भूमिपूजन नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों का लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति मिली है। सड़क, रेल, पेयजल और शहरी विकास के क्षेत्र में लगातार बड़े कार्य हो रहे हैं। बिलासपुर को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। रेलवे के विस्तार, स्टेशनों के उन्नयन और अन्य विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछले दो वर्षों में बिलासपुर नगर निगम को 437 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले समय में शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि नागरिकों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मंगला मुक्तिधाम के लिए 50 लाख रुपये तथा सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

कार्यक्रम को विधायक सुशांत शुक्ला ने भी संबोधित किया। बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर प्रकाश सर्वे, दीपक सिंह, मोहित जायसवाल और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950